

व्यापार भी चलेगा, वाहन भी दौड़ेंगे, एलिवेटेड ब्रिज बनेगा माँडल प्रोजेक्ट

- ▶ श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर का विकास, बदलेगी तस्वीर
- ▶ निकास चौराहा से इंदौर गेट तक एलिवेटेड ब्रिज की फाइट चली
- ▶ 1050 करोड़ से टेंडर निकालने की तैयारी

नवभारत न्यूज उज्जैन. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित एलिवेटेड ब्रिज योजना अब तेजी से धरातल पर उतरती नजर आ रही है. 13 मई 2025 को मुख्यमंत्री ने उज्जैन में एलिवेटेड ब्रिज निर्माण की घोषणा की थी.

सीएम की घोषणा का उद्देश्य विकास को गति देना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और श्रद्धालुओं व व्यापारियों दोनों को राहत देना है. अब इस ऐतिहासिक योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोक निर्माण विभाग की सेतु निगम टीम लगातार सर्वे व तकनीकी कवायद में जुटी हुई है.

ऊपर गाड़ियां, नीचे व्यापार-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया था कि एलिवेटेड ब्रिज इस तरह बनाया जाएगा कि नीचे व्यापार निर्बाध चलता रहे और ऊपर से वाहनों की आवाजाही हो सके. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसी ब्रिज के ऊपर पिलर जोड़कर



मेट्रो संचालन की भी प्लानिंग की जाएगी. उस समय यह घोषणा कई लोगों को असंभव सी लगी थी, लेकिन अब उज्जैन को तेजी से

की योजना पर गंभीरता से काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना सैनिक भेजे रावलापिंडी में हमला कर दिया, तो उज्जैन में भी बिना किसी मकान को छुए ऊपर ही ऊपर एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा. इस सोच के पीछे यही मंशा है कि नीचे कारोबार चलता रहे और ऊपर से ट्रक व अन्य भारी वाहन गुजर सकें.

कमिश्नर कलेक्टर जुटे -कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से लेकर सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह तक इस परियोजना को लेकर पूरी शिदत से लगे हुए हैं. सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सर्वे कार्य लगातार जारी है, ताकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान

महामृत्युंजय द्वार से हरिफाटक तक

इसी तरह इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार से हरी फाटक ब्रिज तक एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं. इस परियोजना की ड्राइंग और डिजाइन एमपीआरडीसी द्वारा तैयार की जा रही है. अनुमान है कि वर्ष 2028 में इसी मार्ग पर सबसे अधिक ट्रैफिक लोड रहेगा. इंदौर-उज्जैन कोरनेन को सिविल लेन में बदला जा रहा है, जिसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. इसी सिविल लेन के ऊपर एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है.

ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके.

सिंहस्थ में बहुउपयोगी

मकोडिया आम चौराहे से चामुंडा चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 25 मीटर होगी. वहीं निकास चौराहे से इंदौर गेट तक बने वाला एलिवेटेड ब्रिज डेड किलोमीटर से अधिक लंबा और लगभग 11 मीटर चौड़ा होगा, जो टूट लेने से बचाए. इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर मध्य अंतिम चरण में है और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

1050 करोड़ से निर्माण -लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अवेन्द्र सिंह ने बताया कि दोनों एलिवेटेड ब्रिज की कुल लागत लगभग 1050 करोड़ रुपये होगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य दोनों शामिल हैं. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आठ तर्क निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकता है और दो वर्षों में एलिवेटेड ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा.

जाम से निजात मिलेगी -इस एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण से उज्जैन शहर में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी, महाकाल मंदिर आने-जाने में सुविधा बढ़ेगी और कई मुख्य मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे. साथ ही सिंहस्थ 2028 के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. यह परियोजना उज्जैन के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है.

4.75 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करेगा बजट

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सीएम के सामने दिया गया प्रेजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 10 फरवरी. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार का बजट 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है. बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, राजकोषीय घाटे को सरकार 4.50 फीसदी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी. राज्य सरकार का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. इससे



एक दिन पहले मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा. नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर मंगलवार को मंत्रालय में पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, बाद में पूरी कैबिनेट के सामने अपर मुख्य

हालांकि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र से लगातार संवाद बनाए हुए है. बजट प्रेजेंटेशन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का ध्यान रखा गया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर बताते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के दृष्टिकोण तथा प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की.

है. इस हिसाब से देखें तो नये बजट में कम से कम 54 हजार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी होगी. बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान यदि किसी एक योजना के लिए होगा तो वह मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना होगा, जिसके लिए इस बार राज्य सरकार 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि

का प्रावधान करेगी. इसी तरह एक बार फिर जल जीवन मिशन के लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के कंधे पर होगी, ये इसलिए कि अब तक केंद्र सरकार ने मिशन के तहत हुए कामों का 8 हजार करोड़ रुपये का बकाया केंद्र सरकार से नहीं मिला है.

दिन में धूप और रात में पड़ रही ठंड

अगले 24 घंटे का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार भोपाल समेत मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर सहित कई हिस्सों में अगले 24 घंटे मौसम में दिन में तेज धूप, रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में हल्की ठंडी हवा चलने की संभावना भी है. वहीं आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. साहज के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

साथ ही उज्जैन और ग्वालियर में खास बदलाव नहीं हुआ. चंबल संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक रहा. डिग्री तक बढ़ा जबकि अन्य क्षेत्रों में तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक रहा.

दो और जिंदगियां बुझीं, आंकड़ा पहुंचा 35



75 साल के बुजुर्ग ने 40 दिन तक किया मौत से संघर्ष

02 साल की मासूम को थी लिवर की गंभीर समस्या



नव भारत न्यूज इंदौर, 10 फरवरी. भागीरथपुरा में गंदे और दूषित पानी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. सोमवार रात एक बुजुर्ग और मंगलवार सुबह एक मासूम बच्ची की मौत के साथ इस त्रासदी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच गई है.

शालिग्राम की बेटी मोना बघेल का कहना है कि उनके पिता को वर्षों पहले लकवा जरूर हुआ था, लेकिन इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी. अचानक उल्टी-दस्त के बाद से ही तबीयत बिगड़ी और वे संभल नहीं सके. वहीं अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीज को पहले से हृदय संबंधी समस्या थी. इधर मंगलवार तड़के करीब 4-30 बजे दो साल की मासूम रिया ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. परिजन बताते हैं कि 27 दिसंबर को उल्टी-दस्त से बीमार होने पर उसे निजी अस्पताल में दिखाया था, जहां कुछ सुधार हुआ, लेकिन बाद में हालत फिर बिगड़ गई. करीब 15 दिन पहले बच्ची को नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने लिवर से जुड़ी गंभीर परेशानी बताई. बाद में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी. परिजनों का सीधा आरोप है कि इलाके में आ रहा दूषित पानी ही बीमारी की जड़ है, जिसने मासूम के शरीर को अंदर तक खोखला कर दिया.

जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों चरम पर हैं. प्रास जांचकारी के अनुसार सोमवार रात 75 वर्षीय शालिग्राम ठाकुर ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था, परिजनों ने बताया कि 2 जनवरी को उल्टी-दस्त की

निकाय और पंचायत चुनाव में आईटी का बेहतर उपयोग करेगा आयोग

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 10 फरवरी. मप्र राज्य निर्वाचन आयोग आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन-2027 में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करेगा. इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में मदद मिलेगी.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस कार्य की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करें. बैठक में केंद्र

संस्था एनआईसीएआई के प्रतिनिधि ने स्थानीय निर्वाचन में मतदाता, मतदान, ट्रेकिंग टूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एवं एआई. आधारित मतदाता सूची एवं मतदाता सत्यापन सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया.

पश्चिम रेलवे ई-निविदा सूचना

APM (Elect), W. Rly. Dahod invites Tender No.22-1-2025-26-18 Date: 09.02.2026. 1. Name of Work: फ्रीडोमडॉर रेलवे कॉलोनी दाहोद में रोशनी के स्तर में सुधार। सहायक परियोजना प्रबंधक (बिजली), सी साइट, फ्रीडोमडॉर, दाहोद - 389160 (गुजरात)। 2. Approximate Cost of the work: ₹ 45,51,022/- 3. Date & time of Submission & opening of E-Tender: Submission Up to 15:00 Hrs on 05.03.2026 and the tenders will be opened at 15:30 Hrs on the same day. 4. The Tender Notice and documents uploaded on the website www.ireps.gov.in / E-Tenders / Works / IR Electrical by this office. V/482 हमें लाइक करें: Facebook.com/WesternRly

रेल सुरक्षा को मजबूत करेगा 'चालक दल ऐप'

भोपाल, 10 फरवरी. भारतीय रेलवे में सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में रनिंग स्टॉफ के लिए गुणवत्तापूर्ण विभ्राम एवं सुविधाजनक उद्धारकों को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.



इसी क्रम में रेलवे द्वारा रनिंग रूम से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए डिजिटल माध्यमों को सशक्त किया जा रहा है. रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित 'चालक दल ऐप' के माध्यम से लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन प्रबंधक को रनिंग रूम से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यह व्यवस्था विभिन्न स्तरों

पेज एक का शेष एमपी में अब परिवार पेंशन का बढ़ा दायरा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है. केन्द्र तथा मप्र शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जायेगा. निलम्बन अर्थात् में अर्थात् तथा नियोक्ता के अंशदान का प्रावधान किया है.

इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया, अंशदान की दर, गणना एवं विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र एवं मृत्यु की दशा में निकास प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले

ये निर्णय भी लिए

- वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति. -उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के आई टी संघर्ष में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी संघर्ष की प्रचलित और भावी भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सफाई के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की स्वीकृति प्रदान की गई. वर्तमान में अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है.

2027 तक देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के प्रयास

12 राज्यों के 124 जिलों में 2 सप्ताह तक चलेगा अभियान

भोपाल 10 फरवरी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 12 राज्यों के 124 जिलों के लिए 'मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 2026' का नई दिल्ली से वचुअल शुभारंभ किया.



समन्वित प्रयास करें. उन्होंने कहा कि दवा का सेवन केवल वितरण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दवा पूरी मात्रा में ली जाए.



केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि भारत सरकार 2027 तक लसीका फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे अभियान के दौरान सभी आवश्यक

संसाधनों और जागरूकता गतिविधियों को सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी अभियान की सफलता और मध्य प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने में निर्णायक होगी. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि इस अभियान में सामुदायिक नेतृत्व और पंचायतों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रदेश में 8 जिलों के 12 विभिन्न विकासखण्डों में प्रशिक्षित दवा सेवकों के माध्यम से बूथ डे एवं घर-घर भ्रमण के दौरान फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन समस्त पात्र हितग्राहियों को कराया जाएगा.

यह अभियान लसीका फाइलेरिया उन्मुलन रणनीति का अहम घटक है. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सहित 12 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों ने वचुअल सहभागिता की.